



भारत का अज्ञपन The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्रादेश से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 417]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1980/भाद्र 15, 1902

No. 417]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1980/BHADRA 15, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग हक्कों के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(प्रौद्योगिक विकास विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1980

का० आ० 760(ए)/18चब/प्राई० डी० आर० ए०/80—भारत सरकार
के उद्योग मंत्रालय (प्रौद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं ० का० आ० 661(ए०), तारीख 7 सितम्बर, 1977 (जिसे इसके पश्चात् उक्त
आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियोग)
प्रशिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चब की
उपधारा (1) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के आरी होने की तारीख से ठीक
पूर्ण प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-प्रक्रमों, करारों
व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिमूल दायित्वों में संबंधित हैं) जिनका
मैसरी यूनियन जूट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता नामक प्रौद्योगिक उपकरण
या ऐसे प्रौद्योगिक अपक्रम का स्वामित्व रखते वाली कम्पनी एक पक्षकार
है या जो उसे प्रौद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, प्रवर्तन एक
वर्ष की अवधि के लिए नियमित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्ण उसके
प्रधीन प्रोब्रूल या उद्भूत होने वाले सभी प्रधिकार, विशेषाधिकार,
आध्यात्म और वायिक उक्त प्रवधि के लिए नियमित रहेंगे;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (प्रौद्योगिक विकास विभाग)
के आदेश संख्या का० आ० 544 (ए)/18चब/प्राई० डी० आर० ए०/78,
तारीख 6 सितम्बर 1978 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 6 सितम्बर,
1979 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि
के लिए और वहाँ दी गई थी;

671GI/80

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (प्रौद्योगिक विकास विभाग)
के आदेश सं ० का० आ० 517(ए०)/18चब/प्राई० डी० आर० ए०/79,
तारीख 6 मितम्बर, 1979 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 6 मितम्बर, 1980
तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अनियन्त्रित अवधि
के लिए और वहाँ दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का सम्मान हो गया है कि उक्त आदेश की
अवधि 6 मितम्बर, 1981 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है,
एक वर्ष की अवधि के लिए और वहाँ दी जाए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम,
1951 (1951 का 65) की धारा 18चब की उपधारा (2) के साथ
पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश
की अवधि, 6 सितम्बर, 1981 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है,
बढ़ाती है।

[का० सं ० 3(4)/77-सी०पू०एस०]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 6th September, 1980

SO. 760(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of
the Government of India in the Ministry of Industry (De-
partment of Industrial Development) No. S.O. 661(E), dated
the 7th September, 1977, (hereinafter referred to as the said
Order), the Central Government, in exercise of the powers
conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of
the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of
1951), had declared that the operation of all contracts, assur-
ances of property, agreements, settlements, awards, standing

orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Union Sure Company Limited, Calcutta or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or Company shall remain suspended for a period of one year, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 544(E), 18FB/IDRA/78, dated the 6th September, 1978, the duration of the said Order was extended for a further period of one year upto and inclusive of the 6th September, 1979;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 517(E)/18FB/IDRA/79, dated the 6th September, 1979, the duration of the said Order was further extended for another period of one year upto and inclusive of the 6th September, 1980.

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year upto and inclusive of the 6th September, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 6th September, 1981.

[F. No. 3(4)/77-CUS]

कानून 761(अ)/18 चला/उद्दिति/अ/80 :—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (श्रीमोंगिक विकास विभाग) के प्रावेश में ० कानून ५४५ (अ)/१८ चला/उद्दिति/लिंग/७५, तारीख २७ सितम्बर, १९७३ (जिसे इसमें आगे उक्त प्रावेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ६५) की धारा १८चल के उपधारा (१) द्वारा प्रदल जनकियों का प्रयोग करने हुए, योग्या बी थी कि—

- (क) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनियित अधिनियमियाँ, ऐसी ऐसे नियमों का लागू नहीं होती; और
- (ख) उक्त प्रावेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदायों, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाई, स्थायी प्रावेशों या अन्य नियन्त्रणों का (जिसमें उक्त उपकरण एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके प्रधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी अधिकारों, विशेषाधिकार, वाच्यताएँ और वायित्वों का प्रवर्तन २६ सितम्बर, १९७६ तक निलम्बित रखेगा;

और उक्त प्रावेश की अवधि ७ सितम्बर, १९८० तक के लिए और बढ़ा दी गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त प्रावेश की अवधि ७ सितम्बर, १९८१ तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए;

अब, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ६५) की धारा १८चल की उपधारा (२) के साथ पांच उपधारा (१) द्वारा प्रदल जनकियों का प्रयोग करने हुए, उक्त प्रावेश की अवधि ७ सितम्बर, १९८१ तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ानी है।

[फारम २(२१)/७५-सी०य००मी०]

S.O. 761(E)/18FB/IDRA/80:—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 545(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that—

- (a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertakings known as Messrs. Sen-Raleigh Limited, Calcutta; and
- (b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 7th September, 1980;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1981;

[F. No. 2(21)/75-Cus.]

कानून 762(अ)/१८ चला/उद्दिति/अ/80 :—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (श्रीमोंगिक विकास विभाग) के प्रावेश में ० कानून ५४९ (अ)/१८ चला/उद्दिति/लिंग/७५, तारीख २७ सितम्बर, १९७३ (जिसे इसमें आगे उक्त प्रावेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ६५) की धारा १८चल की उपधारा (१) द्वारा प्रदल जनकियों का प्रयोग करने हुए, योग्या बी थी कि—

- (क) उक्त प्रधिनियम की सूतीय अनुसूची में विनियिट अधिनियमियाँ, मैमर्स एन्डिनरी इण्डस्ट्रीज (फैब्रिक) प्रावेट लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से जात श्रीमोंगिक उपकरण को लागू नहीं होंगी; और
- (ख) उक्त प्रावेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदायों, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाई, स्थायी प्रावेशों या अन्य नियन्त्रणों का (जिसमें उक्त उपकरण एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके प्रधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी अधिकारों, विशेषाधिकार, वाच्यताएँ और वायित्वों का प्रवर्तन २६ सितम्बर, १९७६ तक निलम्बित रखेगा;

और उक्त प्रावेश की अवधि ७ सितम्बर, १९८० तक के लिए और बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त प्रावेश की अवधि ७ सितम्बर, १९८१ तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए।

अब, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ६५) की धारा १८चल की उपधारा (२) के साथ पांच उपधारा (१) द्वारा प्रदल जनकियों का प्रयोग करने हुए, उक्त प्रावेश की अवधि ७ सितम्बर, १९८१ तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ानी है।

[फारम २(२७)/७५-सी०य००मी०]

S.O. 762(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 549(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that—

- (a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertakings known as Messrs Ancillary Industries (Crarks) Private Limited, Calcutta; and
- (b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 7th September, 1980;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1981;

[F. No. 2(27)/75-Cus.]

कांग्रेस 763(अ)/18 चक्र/उद्धिंविंश्यो/80:—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (प्रौद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० कांग्रेस 546 (अ)/18-चक्र उद्धिंविंश्यो/75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक्र की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि:—

(क) उक्त प्रधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनियिष्ट प्रधिनियमियां, ऐनमें एनियरिंग इंडस्ट्रीज (लग्स) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात श्रीद्योगिक उपकरण को लागू नहीं होगी; और

(ब) उक्त आदेश के राजावत में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रदृश भूमि संविदाओं, मम्पनि के हस्तांतरण पद्धों, करारों, अवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जिसमें उक्त उपकरण एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोदृशत या उद्भूत होने वाले सभी प्रधिकारों, विशेषाधिकार, वाध्यताएँ और वायित्वों का प्रवर्तन 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेगा;

और उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए और बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक्र की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ाती है।

[फांग्रेस 2(28)/75-नी०य०सी०]

S.O. 763(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 546(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that—

- (a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertakings known as (Messrs Ancillary Industries (Lugs) Private Limited, Calcutta; and
- (b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 7th September, 1980;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1981;

[F. No. 2(28)/75-Cus.]

कांग्रेस 764 (अ)/18 चक्र/उद्धिंविंश्यो/80 :—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (प्रौद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० कांग्रेस 548 (अ)/18 चक्र/उद्धिंविंश्यो/75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक्र की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि:—

(क) उक्त प्रधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनियिष्ट प्रधिनियमियां, ऐनमें एनियरिंग इंडस्ट्रीज (फोर्म्स) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात श्रीद्योगिक उपकरण को लागू नहीं होगी; और

(ब) उक्त आदेश के राजावत में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, मम्पनि के हस्तांतरण पद्धों, करारों, अवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जिसमें उक्त उपकरण एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोदृशत या उद्भूत होने वाले सभी प्रधिकारों, विशेषाधिकार, वाध्यताएँ और वायित्वों का प्रवर्तन 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेगा;

और उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए और बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक्र की उपधारा (2)

के साथ परिवर्तन उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख थी है, और बढ़ाई गई है।

[फा०सं० 2(29)/75-मी० य० सी०]

S.O. 764(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 548(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that —

- (a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertakings known as Messrs Ancillary Industries (Forgings) Private Limited, Calcutta; and
- (b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 7th September, 1980;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1981;

[F. No. 2(29)/75-Cus.]

का०सा० 765 (म)/18 चल०उ०वि०वि०व०/80.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के मूलपूर्व उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय (शोषणिक विकास विभाग) के भादेश से० का०सा० 547 (म)/18 चल० /उ०वि० वि०व०/75, सारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियोग) 1951 (1951 का 65) की भारा 18 ज्ञ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि :—

- (क) उक्त प्रधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनियिष्ट प्रधिनियमितियाँ, भैसर्व सेन एवं पंडित हण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात शोषणिक उपकरण को लागू नहीं होगी; और

(घ) उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रकृत सभी रूपदाताओं, अम्पाल के हल्लान्नरण पत्रों, करारों व्यवस्थापनों, पंचांगों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (जिसमें उक्त उपकरण एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके प्रधीन प्रोटोकॉल या उत्प्रसूत होने वाले सभी प्रधिकारों, विणेशाधिकार, आड्यनाय और वायित्वों का प्रबंधन 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रखेगा;

और उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए और बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियोग) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) की भारा 18 ज्ञ की उपधारा (2) के साथ परिवर्तन उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख थी है, और बढ़ाती है।

[फा०सं० 2(30)/75-मी० य० सी०]
बं० राय, संयुक्त सचिव

S.O. 765(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 547(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that —

- (a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertakings known as Messrs, Sen and Pandit Industries Limited, Calcutta; and
- (b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 7th September, 1980;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1981;

[F. No. 2(30)/75-Cus.]

B. ROY, Jt. Secy.